इस साल डेट फंडों का रिटर्न दमदार

अभिषेक कुमार
मुंबई, 20 दिसंबर

ब्याज दर में कोई बदलाव न होने के बावजूद डेट म्युचुअल फंड (एमएफ) योजनाएं प्रदर्शन के लिहाज से 2024 पिछले चार वर्षों में सबसे उम्दा कैलेंडर वर्ष रहने जा रहा है। डेट फंडों के एक साल के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि कई योजनाओं ने वर्ष 2024 में दो अंक का रिटर्न दिया है। लंबी अवधि वाले डेट फंडों का प्रदर्शन शानदार रहा। ये फंड योजनाएं सिर्फ टॉप रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश करती हैं। इस श्रेणी की सभी सात योजनाओं ने पिछले एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है।

वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश गिल्ट फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड भी 9 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय वर्ष के दौरान हुई कई सकारात्मक गतिविधियों को दिया जा सकता है, जिनमें वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होना और राजकोषीय समझदारी शामिल है।

ट्रस्ट म्युचुअल फंड के मुख्य कार्याधिकारी संदीप बागला ने कहा, 'बॉन्ड यील्ड ने साल की शुरुआत सख्त तरलता हालात, ऊंची मुद्रास्फीति और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सतर्क रुख के कारण ऊंचे स्तर पर शुरुआत की। साल के दौरान कई कारक घरेलू बॉन्ड के लिए सकारात्मक साबित हुए। समग्र महंगाई में कमी आने लगी और मुख्य महंगाई, यानी खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई।'

इस साल भारत सरकार के बॉन्डों को जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया। घरेलू बॉन्डों को भी 2025 में एफटीएसई रसेल ईएमजीबी इंडेक्स और ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'सरकारी बॉन्डों को कुछ वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया गया। इससे सुनिश्चित हुआ कि उन विदेशी निवेशकों की लगातार खरीद बनी रहेगी जो इन सूचकांकों पर नजर रखते हैं।'

10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड वर्ष के शुरू में 7.17 फीसदी पर था जो अब 6.79 फीसदी पर है। यील्ड में गिरावट बॉन्डधारकों के लिए सकारात्मक होती है, क्योंकि कीमतें और यील्ड का विपरीत संबंध होता है। यील्ड में उतार-चढ़ाव मुख्यतः मांग-आपूर्ति के गणित, ब्याज दरों में बदलाव तथा अन्य घरेलू वृहद एवं वैश्विक कारकों पर निर्भर करता है। मनी मार्केट फंड, कम अवधि वाले फंड और अल्ट्रा-शॉर्ट अवधि वाले फंड जैसे कम निवेश अवधि वाले फंड भी 2024 में कई वर्षों में ऊंचे रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। 19 दिसंबर तक उन्होंने एक वर्ष की अवधि में करीब 8 प्रतिशत रिटर्न दिया था। फंड प्रबंधकों के अनुसार 2024 की तेजी 2025 में भी बरकरार रहने की संभावना है। आरबीआई द्वारा दर कटौती की संभावना को अगले साल डेट बाजार के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

बंधन एएमसी में फिक्स्ड इनकम में प्रमुख सुयश चौधरी ने कहा, 'हमारा मानना है कि खपत में कमी के साथ वृद्धि चक्रीय रूप से धीमी रहेगी और प्रस्तावित नए टैरिफ और चीन द्वारा अपनी अतिरिक्त क्षमता का निर्यात करने के दबाव से व्यावसायिक धारणा के संबंध में अनिश्चितता दिख सकती है।' सुस्त आर्थिक वृद्धि के कारण केंद्रीय बैंक अगले वर्ष की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।'

बीते चार वर्षों में सबसे शानदार रहा 2024

- वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने और आपूर्ति कम होने से रिटर्न को मिला दम
- ये फंड योजनाएं सिर्फ टॉप रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश करती हैं
- इस श्रेणी की सभी सात योजनाओं ने पिछले एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है
- अगले साल दर कटौती की संभावना डेट बाजार के लिए अनुकूल
- गिल्ट फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड भी 9 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं

सेबी ने डेटा शेयरिंग नीति में एकरूपता पर जोर दिया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज को निर्देश दिया कि वे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले शोध और शोध प्रकाशनों के लिए डेटा साझा करने के लिए समान नीति अपनाएं।

इन मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) को ऐसे डेटा को दो बास्केट में अलग करने के लिए कहा गया है, एक जिसे सार्वजनिक तौर पर साझा किया जा सकता है और दूसरा जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है। पहले बास्केट में सिर्फ सकल और विश्लेषित डेटा होंगे, जिसमें नियामकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग और खुलासा किए जाने वाले डेटा भी शामिल होंगे।

सेबी ने कहा कि डेटा को अलग अलग रखने का मकसद सार्वजनिक डोमेन में किसी भी व्यक्तिगत, संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का सार्वजनिक करने से रोकना है।

दूसरे बास्केट में केवाईसी जानकारी, ट्रेड लॉग, किसी इकाई या व्यक्ति की होल्डिंग जानकारी आदि शामिल हैं, जिसमें इकाई या व्यक्ति की पहचान शामिल है। इसके अलावा, यहां तक कि गुप्त डेटा भी सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग व्यक्ति या इकाई की पहचान के लिए किया जा सकता है। एमआईआई को प्रत्येक बास्केट के तहत डेटा की सूची दो महीने के भीतर सेबी को मंजूरी के लिए साझा करने के लिए कहा गया है। *बीएस*

ऐक्सेंचर के नतीजों का असर

भारतीय आईटी फर्मों के प्रति उत्साह बढ़ा

निकिता वशिष्ठ
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

वैश्विक सलाहकार ऐक्सेंचर की पहली तिमाही की आय के आधार पर शुक्रवार को विश्लेषकों ने कहा कि भारत का आईटी उद्योग एक कठिन दौर के बाद अब लगातार आय सुधार के लिए तैयार है।

फॉर्च्यून-500 में शामिल कंपनी ऐक्सेंचर का मुख्यालय डबलिन में है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की सितंबर-नवंबर तिमाही में 17.7 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। डॉलर के लिहाज से यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत और स्थानीय मुद्रा में 8 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व आय लगभग 24 करोड़ डॉलर थी जो कंपनी के ऊपरी अनुमानित दायरे से अधिक है। कंपनी सितंबर-अगस्त वित्त वर्ष पर अमल करती है। कंपनी के वैश्विक कर्मियों का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत में है। भारतीय आईटी कंपनियां वैश्विक मांग का आकलन करने के लिए ऐक्सेंचर के रुझानों पर नजर रखती हैं।

ऐक्सेंचर ने वित्त वर्ष 2025 की राजस्व वृद्धि का अपना स्थानीय मुद्रा अनुमान पहले के 3-6 फीसदी से बढ़ाकर 4-7 फीसदी कर दिया है। एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज के विश्लेषक लार्जकैप में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो और एलटी-आईमाइंडट्री पर दांव लगा रहे हैं। मिडकैप में उनके पसंदीदा शेयरों में सोनाटा सॉफ्टवेयर, सायंट, ईक्लर्क्स और बिरलासॉफ्ट शामिल हैं।

ऐक्सेंचर की पहली तिमाही

ऐक्सेंचर के प्रबंधन का कहना है कि पहली तिमाही की राजस्व वृद्धि हेल्थ एवं पब्लिक सर्विसेज व्यवसाय (पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि), उत्पाद (10 प्रतिशत), दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी (7 प्रतिशत), संसाधन (6 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाओं (4 प्रतिशत) के कारण हुई।

आउटसोर्सिंग से राजस्व स्थानीय मुद्रा के लिहाज से 11 फीसदी बढ़ा, जिसे टेक्नोलॉजी-प्रबंधित सेवाओं में दो अंक की वृद्धि और परिचालन में मजबूत एक अंक की वृद्धि से मदद मिली। कंसल्टिंग व्यवसाय सालाना आधार पर स्थानीय मुद्रा में 6 फीसदी बढ़ा। अमेरिका (उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका समेत) में व्यवसाय स्थानीय मुद्रा में 11 फीसदी बढ़ा जबकि यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में 6 फीसदी और एशिया प्रशांत में 4 फीसदी बढ़ा।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की सितंबर-नवंबर तिमाही में 17.7 अरब डॉलर का राजस्व कमाया

नोमूरा के विश्लेषकों का कहना है, 'हालांकि डिस्क्रेशनरी मांग में मजबूत सुधार आने में कुछ तिमाहियों का वक्त लग सकता है। लेकिन इसके और खराब होने की संभावना नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे कवरेज वाले लार्जकैप के लिए राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2026 में सुधरेगी।' नोमूरा ने लार्जकैप में इन्फोसिस और विप्रो पर 'खरीदें' रेटिंग और एलटीआईमाइंडट्री, एम्फेसिस तथा एलटीटीएस पर 'घटाएं' रेटिंग दी है।

ऐक्सेंचर का आउटलुक

ऐक्सेंचर ने वित्त वर्ष 2025 में परिचालन मार्जिन वृद्धि के लिए अपना अनुमान बरकरार रखा है। कंपनी ने परिचालन मार्जिन 80-110 आधार अंक बढ़कर 15.6-15.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। समायोजित परिचालन मार्जिन 10-30 आधार अंक तक बढ़कर 15.6-15.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण वाले परिवेश और सीमित बजट के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में कंसल्टिंग व्यवसाय मध्यम एक अंक में और प्रबंधित सेवाएं मध्य से ऊंचे उक अंक में बढ़ेंगी।

एसएमई आईपीओ के लिए नए नियम

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 दिसंबर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के एक दिन बाद ही नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने लघु और मझोले उद्यमों (एसएमई) की सूचीबद्धता के लिए नई पात्रता शर्तें लागू कर दी हैं।

एनएसई ने आज 20 दिसंबर को जारी सर्कुलर में कहा है, ' एनएसई इमर्ज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने के इच्छुक एसएमई को उन सभी अतिरिक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जिनको सेबी ने अपनी 208वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी है।' आमतौर पर बाजार नियामक की अधिसूचना जारी होने के बाद ही मानदंड प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन एनएसई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्हें 19 दिसंबर से ही लागू कर दिया है।

एनएसई ने कहा, 'एसएमई फ्रेमवर्क पर अतिरिक्त शर्तें/मानदंड सैद्धांतिक मंजूरी पाने के लिए 19 दिसंबर 2024 को या उसके बाद दाखिल सभी डीआरएचपी पर लागू होंगे। गुणवत्ता जांच के लिए एनएसई द्वारा निर्धारित अन्य मौजूदा शर्तें बनी रहेंगी और पहले की तरह ही लागू रहेंगी।'

अब, जारीकर्ता केवल तभी पात्र होंगे जब उनके पास मसौदा दाखिल करने के समय पिछले तीन वित्त वर्षों में से किसी दो के लिए 1 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हो। इसके अलावा, शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए रखी जाने वाली इक्विटी का आकार भी कुल निर्गम के 20 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है। सेबी ने एसएमई के हित में कई नियमों को सरल बनाने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है जो एनएसी के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। वित्त वर्ष 2012 से अक्टूबर 2025 तक एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध 572 कंपनियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इनमें से 140 मेनबोर्ड पर आ गई हैं। एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिहाज से सितंबर में 1,194 करोड़ रुपये के साथ सर्वाधिक ऊंचा स्तर दर्ज किया गया था, लेकिन अक्टूबर में यह आंकड़ा घटकर 980 करोड़ रुपये रह गया।

6 निर्गमों को शुक्रवार को संपूर्ण बोलियां

बीएस संवाददाता
मुंबई, 20 दिसंबर

डैम कैपिटल एडवाइजर्स, सनातन टेक्सटाइल्स, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, ममता मशीनरी और ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ को 1.24 से 37.75 गुना तक बोलियां मिली हैं। वहीं शुक्रवार से खुले वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सेनोरेस फार्मास्युटिकल्स और कैरारो इंडिया को 0.09 से 1.78 गुना तक सबसक्राइब किया गया।

संयुक्त रूप से इन आठ निर्गमों से 5,501 करोड़ रुपये जुटाए जाने हैं। डैम कैपिटल एड-वाइजर्स, सनातन टेक्सटाइल्स, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, ममता मशीनरी और ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ सोमवार को बंद हो जाएंगे और अन्य शेष के लिए मंगलवार तक बोलियां लगाई जा सकेंगी। इससे दिसंबर इस साल आईपीओ के लिए बेहद व्यस्त महीना बन गया है। कंपनियां आमतौर पर दिसंबर में आईपीओ लाने से बचती हैं क्योंकि उन्हें साल के अंत में होने वाली छुट्टियों के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सीमित भागीदारी की चिंता रहती है। हालांकि, नए इश्यू और लिस्टिंग लाभ की मजबूत मांग ने ऐसी कंपनियों को बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस बीच, शुक्रवार को बाजार में दस्तक देने वाला इंटरनैशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट अपने निर्गम भाव के मुकाबले पहले दिन 12.75 फीसदी तेजी के साथ बंद हुआ। यह शेयर अपने निर्गम भाव के मुकाबले 21 फीसदी तेजी के साथ 504.85 पर खुला था। हालांकि बाद में कुछ बढ़त गंवाते हुए आखिर में 470.15 पर बंद हुआ। सूचीबद्धता के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 20,318 करोड़ रुपये हो गया है।

एम्फी के 'म्युचुअल फंड सही है' विज्ञापनों के खिलाफ जनहित याचिका दायर

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 दिसंबर

बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) में मांग की गई है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिए जाएं कि उसने निवेशक जागरूकता और सुरक्षा उपायों के तहत 'भ्रामक' और 'गुमराह' करने वाले विज्ञापन अभियानों के लिए एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) को जो अनुमति दी है, उसे रद्द कर दे।

याची पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने आरोप लगाया है कि एम्फी 'बिना किसी आधार या तर्क के लापरवाही से यह प्रचार कर रहा है कि म्युचुअल फंड सही हैं।' याची ने आरोप लगाया है, 'विज्ञापन अभियान पूरी तरह से निराधार, लापरवाह, झूठे, आधारहीन और गुमराह करने वाले हैं, जिनमें सकारात्मक फीचर्स पर तोड़-मरोड़कर जोर दिया गया है।' एम्फी के विज्ञापनों की तुलना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और खुद सेबी जैसी अन्य संस्थाओं के विज्ञापनों से करते हुए याची ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त विज्ञापन किसी भी कारोबार को बढ़ावा नहीं देते हैं, उनका कोई वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं है। वे पूरी तरह सार्वजनिक भलाई के लिए हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बंबई उच्च न्यायालय से सेबी को निर्देश देने का किया अनुरोध

याचिका में कहा गया है, 'एम्फी द्वारा प्रचारित विज्ञापन अभियानों में निवेशक शिक्षा या जागरूकता जैसा कोई भी तत्व नहीं है। ये विज्ञापन अभियान म्युचुअल फंड की विशेषताओं और फीचर्स, इनकी सीमाओं/बाधाओं आदि के बारे में प्रकाश नहीं डालते या उल्लेख नहीं करते, बल्कि बिना किसी आधार या गुणवत्ता के केवल इस बात का जोरदार समर्थन करते और राय देते हैं कि म्युचुअल फंड सही हैं, महज एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ।'

याची ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन वाणिज्यिक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य केवल एम्फी के सदस्यों को लाभ पहुंचाना है, न कि निवेशकों की सुरक्षा की ज्यादा परवाह करना। कानून के जानकारों का कहना है हाई कोर्ट ने इस मामले में बाजार नियामक को नोटिस भेजा है।

क्रेडिट कार्ड भुगतान में देर तो लगेगा ज्यादा ब्याज!

पृष्ठ 1 का शेष

एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में कहा था, 'अगर आरबीआई को देश के वित्त और अर्थव्यवस्था का प्रहरी में से एक माना जाता है और मौजूदा ऋण स्थितियां ऐसी हैं कि उसे नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे विचार में देय तिथि से पहले बकाये को भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों से सालाना 36 से 49 फीसदी तक ब्याज वसूला जाता है और यह कर्ज लेने वालों का एक तरह से शोषण है और ऐसा करने वाले बैंकों को नियंत्रित नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं है।'

आयोग ने कहा कि आरबीआई ने विभिन्न परिपत्र जारी कर कहा है कि बैंकों को अत्यधिक ब्याज दर नहीं वसूलनी चाहिए लेकिन वह यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि वह किसे अत्यधिक या सूदखोरी वाला ब्याज दर कहेगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि 30 फीसदी ब्याज दर की सीमा हटाए जाने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट कार्ड बिल का देर से भुगतान करने के मामले में ब्याज दर तय करने में सहूलियत होगी। सिरिल अरमचंद मंगलदास में पार्टनर गौहर मिर्जा ने कहा, 'इससे देय तिथि के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। बैंक बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत जोखिम आकलन के आधार पर भी ब्याज दर तय कर सकेंगे। इससे बैंकों को क्रेडिट कार्ड कारोबार से ज्यादा आय मिल सकता है।'

बैंकों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश करने वाले एसएनजी ऐंड पार्टनर में मैनेजिंग पार्टनर (विवाद समाधान) संजय गुप्ता संजय गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस फैसले से देश में क्रेडिट कार्ड उद्योग को बड़ी राहत मिली है।

APPOINTMENTS

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
Baroda Global Shared Services Ltd.

(A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BANK OF BARODA)
REGD. OFFICE – 5TH FLOOR, BARODA SUN TOWER, C – 34, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI 400 051.
CIN NO. U74999MH2017GOI292430

(A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BANK OF BARODA)

PAN India level applications are invited from eligible candidates for the below positions at **Baroda Global Shared Services Ltd.** located in **Gift City, Gandhinagar, Gujarat**.

Function	Job Role	Location
Digital Banking	Team Member	Mumbai/ Vadodara
Collections	Dialer- Assistant Manager	Vadodara
	FOS	Vashi-Mumbai
	Debt Recovery Agent	Gandhinagar/ Bengaluru
RAPC	Apprenticeship/ Executive	Gandhinagar
Finance & Accounts	Senior Manager	Gandhinagar
Financial Inclusion	State Head	Bilaspur/ Chandigarh
Human Resource	Operations- Manager	Gandhinagar
Information Technology	Information Technology Lead	Gandhinagar
Legal & Compliance	Company Secretary	Gandhinagar
Retail Sales	Chief Business Officer	Mumbai
	Sales Officers (AL/ HL/ EL)	PAN India

For further details on the above, please visit the careers section on www.bgss.in
Addendum / Modifications if any shall be notified only on www.bgss.in
Applicants should refer to the same before submission of their application by e-mailing their resume on recruitment@bgss.in

Last Date for Application- 15th January 2025
Place: Gandhinagar, Gujarat

S/D-Human Resources
Baroda Global Shared Services ltd.

NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत।

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन ३२ (५) (ए) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

यहां सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कंपनियों के इक्विटी शेयरों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन ३२ (५) (ए) ("असूचीबद्धता विनियम"), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, १९५७ के नियम २१ (२) (बी) ("एक्सचेंज") के अनुसार १७ अक्टूबर, २०२४ से असूचीबद्ध कर दिया गया है क्योंकि इन्हें बीएसई लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है।

बीएसई द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी

कंपनियों का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता•	उचित मूल्य (रु. प्रति शेयर)	प्रवर्तकों के नाम	प्रवर्तकों के पते •
सेलेस्टियल बायोलैब्स लिमिटेड प्लॉट नंबर ५९, रोड नंबर १२, एपीआईआईसी टेक पार्क आईडीए नचाराम, हैदराबाद ५०००७६	१.१७/-	आदित्य नारायण सिंह	फ्लैट नंबर ६-३-७८, १०१ शिव उमा सदन, हस्तिनापुरी कॉलोनी, सैनिकपुरी तिरुमालागिरी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ५०००९४ और प्लॉट नंबर २३१-ए, रोड नंबर १२ एमएलए कॉलोनी बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ५०००३४
		अमित कुमार सिंह	फ्लैट नंबर ३४ /१३२ / ३ कृपा कृष्णा अपार्टमेंट रोड नंबर क्रिसैट ब्लॉक भरणी, कॉलोनी सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना - ५०००९४ और फ्लैट नंबर १०१, प्लॉट नंबर ७८ शिव उमा सदन हस्तिनापुरी कॉलोनी, सैनिकपुरी रोड सिकंदराबाद, तेलंगाना - ५०००९४
		पद्मा सिंग	फ्लैट नंबर १०१, प्लॉट नंबर ७८ शिव उमा सदन हस्तिनापुरी कॉलोनी, सैनिकपुरी रोड सिकंदराबाद, तेलंगाना ५०००९४
		नितिन कुमार सिंह	फ्लैट नंबर ६-६-७८, १०१ शिव उमा सदन अपार्टमेंट, हस्तिनापुरी कॉलोनी, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना - ५०००९४ और नंबर ३४-१३२/३ कृपा कृष्णा अपार्टमेंट, सैनिकपुरी, भरणी क्लाइ, सिकंदराबाद, तेलंगाना - ५०००९४
		अनीता सिंह	फ्लैट नंबर १०१, प्लॉट नंबर ७८, शिव उमा सदन, हस्तिनापुरी कॉलोनी सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश ५०००९४
जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुकान नंबर १, दादलानी पार्क, पाइपलाइन रोड के पास, बालकुम, ठाणे (पश्चिम) ४००६०८, महाराष्ट्र।	१२.९४/-	आदित्य राजेंद्र पारीख	३१ योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड गामदेवी, मुंबई-४००००७ और फ्लैट नंबर ७, ३७वीं मंजिल, चित्रकूट बिल्डिंग, अल्टामाउंट रोड, मुंबई - ४०००२६
		राजेंद्र जी पारीख	३१, योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड, मुंबई - ४००००७ और पाडा नं.३, बाल्कुम, ठाणे ४००६०८
		जागृति राजेंद्र पारीख	फ्लैट नंबर ११०२, ११वीं मंजिल, लोढा प्रिमेरो बिल्डिंग, एन एम जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - ४०००११ और ३१, योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड, मुंबई - ४००००७
		कोर्पस फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड #	शॉप नंबर १, दादलानी पार्क, पाइपलाइन रोड के पास, बाल्कुम, श्रीरंगनगर, ठाणे ४००६०८
		जागृति सिक्योरिटीज लिमिटेड	१६ गुंडेचा चैंबर्स, नागिनदास मास्टर रोड, मुंबई - ४०००२३

*** एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।**
 # एमसीए के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।
ध्यानार्थः
सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के अनुसार, अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

a. असूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन ३४(१) के अनुसार, कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इसके प्रवर्तक और उनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुंच पाएंगी या किसी इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता की मांग नहीं करेंगी या इस असूचीबद्धता की तारीख से दस (१०) वर्ष की अवधि तक प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

b. ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है -
   (i) ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट लाभ जैसे लाभांश, राइट्स, बोनस शेयर, शेयर विभाजन आदि प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक निष्क्रिय रहेंगे, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित इन विनियमों के विनियमन ३३ के उप-विनियमन (4) का अनुपालन करते हुए पब्लिक शेयरधारकों को निकास विकल्प प्रदान नहीं करते हैं;
   (ii) अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्ण- कालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि क्लॉज (ए) में उल्लिखित निकास विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

c. सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रवर्तकों पर है।

d. असूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन ३३(४) के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख से तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे, जो सार्वजनिक शेयरधारकों की अपनी शेयर रखने की इच्छा पर निर्भर करेगा।

e. असूचीबद्धता विनियमन के विनियमन ३३ (५) के अनुसार, यदि विनियमन ३३ के उप-विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान उप-विनियम (४) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सभी शेयरधारकों को नहीं किया जाता है तो प्रवर्तक ऐसे सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के तहत अपने शेयर पेश करते हैं।

किसी भी प्रश्न के लिए असूचीबद्धता समिति, सूचीबद्धता विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाजा, सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ को संपर्क किया जा सकता है।
संपर्क नंबरः +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४),
ई-मेलः vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in, cc के साथ dl-insp-enf-delisting@nse.co.in.

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से ऊपर निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक्सचेंज की तरफ से
स्थानः मुंबई
दिनांकः २१ दिसंबर २०२४
Nifty50